श्री नरेन्द्र मोहन : सभापति जी, मंत्री जी ने सड़क के बारे में जो उत्तर दिया है, उस संदर्भ में मुझे पूछना है कि क्या रक्षा मंत्रालय इस बात को आवश्यक मानता है कि नई सड़क बनाई जाए, क्योंकि वहां पर जो स्थिति है वह यह है कि वहां वर्ष में आठ महीने, नौ महीने तक जो सड़क है, वह बंद हो जाती है। ऐसी स्थिति में नई सड़क बनाए जाने की बारे में चर्चा कई बार हुई लेकिन क्या प्रतिरक्षा मंत्रालय इसको अन्यावश्यक मानता है ? अगर मानता है तो उसने इस बारे में क्या किया है ?

श्री जार्ज फर्नान्डीज : सभापति महोदय प्रतिरक्षा मंत्रालय इस सड़क की आवश्यकता को जरूर महसूस करता और शायद अत्यधिक महसूस करता है । लेकिन जब पैसे का प्रश्न आता है तब हमारे सामने प्राथमिकता की बात आ जाती है । आज जम्मू-कश्मीर के इलाके में और विशेषकर उन इलाकों में जहां पर वहां के लोगों को कई बार हमलों का सामना करना पड़ रहा है, उन इलाकों में सड़कें बनाने को प्राथमिकता दी गई है । जो भी सड़कों के लिए आबिटन हुआ है वह उन इलाकों में इस वक्त जा रहा है । इसलिए प्रश्न प्राथमिकता का है । जहां मारी संघर्ष है, उस इलाके में सड़कों को प्राथमिकता देना हमारा संकल्प है ।

*245. [The questioner (Shri S. Agniraj) was absent. For Answer, vide col.....infra]

*246. [The questioner (Shri Krishna Kumar Birla) was absent. For Answer, vide col.....infra]

*247. [The questioner (Shri Parag Chalika) was absent. For Answer, vide col.....infra]

जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत मध्य प्रदेश द्वारा धनराशि का उपयोग

***248. श्री अनन्तराय देवशंकर दवे :** क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा क्रियान्वित की जा रही जवाहर रोजगार योजना और अन्य उन्मूलन कार्यक्रमों के अन्तर्गत मध्य प्रदेश को विगत तीन वर्षों में प्रति वर्ष कितनी-कितनी धनराशि आबंटित की गई ;

(ख) उक्त धनराशियों का जिला-वार और कार्यक्रम-वार कितना-कितना कम उपयोग किया गया अथवा पूरी तरह उपयोग नहीं किया गया;

(ग) सरकार ने उक्त कार्यक्रमों के अन्तर्गत धनराशियों का पूरा-पूरा उपयोग सुनिश्चित करने के लिये क्या-क्या उपाय किये हैं ; और

(घ) राज्य के विदिशा जिले में प्रति व्यक्ति उपलब्ध करायी जाने वाली धनराशि का ब्यौरा क्या है ?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बाबागौडा पाटील) : (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) और (ख) विगत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष में मध्य प्रदेश में सरकार द्वारा चलाई जा रही जवाहर रोजगार योजना तथा अन्य गरीबी उपशमन कार्यक्रमों यथा, सुनिश्चित रोजगार योजना, दस लाख कुओं की योजना, इंदिरा आवास योजना, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, ग्रामीण युवा स्वरोजगार प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा ग्रामीण महिला एवं बाल विकास योजना के अन्तर्गत आबंटित, प्रयुक्त तथा अप्रयुक्त राशि के जिलावार ब्यौरे अनुपत्र में दिये गये हैं । [देखिये परिशिष्ट 185, अनुपत्र सं. 47]

(ग) उक्त कार्यक्रमों के अन्तर्गत निधियों के पूर्ण उपयोग को सुनिश्चित करने के लिये सरकार ने एक बृहत् निगरानी व्यवस्था बनाई है, जिसमें मासिक प्रगति रिपोर्टें, वित्तीय रिटर्नें/लेखा-परीक्षण रिपोर्टें, राज्य सरकार के अधिकारियों द्वारा गहन निरीक्षणें, क्षेत्रीय अधिकारियों की योजना, विभिन्न समितियां यथा, संसदीय परामर्शदात्री/स्थायी समिति और जिला ग्रामीण विकास एजेंसी के परियोजना निदेशकों तथा ग्रामीण विकास के राज्य सचिवों की बैठकें शामिल हैं ।

(घ) वर्ष 1991 की आबादी के आधार पर 1998–99 में ग्रामीन क्षेत्रों में गरीबी उपशमन और रोजगार सृजन कार्यक्रमों के लिए विदिशा जिले में प्रति व्यक्ति दी जाने वाली राशि लगभग 73.00 रुपये (मांग पर आधारित सुनिश्चित रोजगार योजना को छोड़ कर) है ।

श्री अनन्तराय देवशंकर दवे : सभापति महोदय, माननीय मंत्री जो जो स्टेटमेंट

सभा पटल पर रखा है, उसमें मध्य प्रदेश में तीन सालों में जे० आर० वाई०, ई० ए० एस०, एम० डब्ल्यू० एस०, आई० आर० डी० पी० ट्राइसेम और दवाकरा में यह जो 6 स्कीम चल रही हैं उनमें जो उन्होंने आंकड़े बताए हैं, तीनों योजनाओं में जो राशि खर्च नहीं की गई है, उसकी संख्या बहुत है। करोड़ों रूपया जब सेंट्रल गवर्नमेंट यहां से भेजती है तो इतना पैसा खर्च क्यों नहीं किया गया, इसकी क्या वजह है, यह मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं ?

SHRI BABAGOUDA PATIL: Sir, Madhya Pradesh Government is utilising the Central funds to our satisfaction. Unspent money to the extent of 25 per cent is permissible at the end of each year. If the hon. Member sees the performance of the State Government, he will find that under JRY in 1996-97, the available money was Rs. 231 crores and the unspent money was only Rs. 33 crores. In 1997-98, the available money was Rs. 282 crores and the unspent money was only Rs. 36 crores. This year, 1998-99, the performance is still better. The available money is Rs. 190 crores and the unspent money is Rs. 77 crores. Still there is a three-month period to utilise that money. Under EAS also you can find the performance of the State Government. Except DWCRA and Million Wells Scheme, under all the schemes, the performance is good.

श्री अनन्तराय देवशंकर दवे : सभापति जी, मेरा दूसरा सवाल इन स्कीमों के अन्दर से ही है। लोक सभा में माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत स्पष्ट रूप में कहा था कि आई० आर० डी० पी० स्कीम जो है जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का पैसा स्टेट में हर डिस्ट्रिक्ट में जाता है लेकिन आई० आर० डी० पी० का चेयरमेन जिला पंचायत का डी० डी० ओ० स्टेट गवर्नमेंट की सूचना से वह लोग बनाते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से कहा था लेकिन आई० आर० डी० पी० का चेयरमैन आज के दिन तक सरकारी अफसर ही है। उनकी जगह जिला परिषद् के अध्यक्ष को बनाना चाहिए और मोनिटेरिंग कमेटी का चेयरमन भी जिला परिषद् के अध्यक्ष को बनाना चाहिए। कई स्टेटों में यह काम हो गया है लेकिन कई राज्यों में यह नहीं हुआ है। में मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि कौन कौन सी स्टेट में अभी तक जिला परिषद् के प्रमुख को आई० आर० डी० पी० का अध्यक्ष नहीं बनाया गया। सेंट्रल गवर्नमेंट की सूचना जाने के बावजूद भी राज्य सरकारें इनको यदि चेयरमैन नहीं बनाती हैं तो आप उस स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ क्या कदम उठाना चाहते हैं ?

SHRI BABAGOUDA PATIL: Sir, we are writing to all the State Governments in this regard. Zilla Panchayat Chairman should be the DRDA President. All the State Governments are taking into consideration the suggestion of making the Zila Panchayat Chairman as the President of DRDA. About the selection of IRDP beneficiaries, now the Gram Sabha is identifying the beneficiaries. In Madhya Pradesh olso, the Zilla Panchayat Chairman is the President of the DRDA.

श्री अनन्तराय देवशंकर दवे : सभापति महोदय, मैंने सवाल किया था कि कौन कौन से राज्य में अभी तक नहीं हुआ है और उन राज्यों के खिलाफ आप क्या कदम उठाने जा रहे हैं ?

SHRI BABAGOUDA PATIL: I want a specific notice for that.

MR. CHAIRMAN: The Question was relating to Madhya Pradesh and please confine yourself to that only.

श्री नागेन्द्र नाथ ओझा : सभापति जी, धन्यवाद।

मैं जानना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश के अन्दर गरीबी उन्मूलन योजनाओं के कारण, इनके इंप्लीमैंटेशन के चलते गरीबी में कितनी कमी आई है ? एक, और दूसरा, जैसे कि विभिन्न राज्यों से यह रिपोर्ट

आ रही है और मध्य प्रदेश के बारे में भी सच है कि जो इंप्लीमेंट एश्योरेंस स्कीम है उसको सिर के बल खड़ा कर दिया गया है यानी इन योजनाओं का चयन गरीबों के जरिए किया जाना है लेकिन वहां यह डी० आर० डी० एस० के जरिए किया जा रहा है। तो क्या इसके बारे में जानकारी मंत्री महोदय जी को है कि इन योजनाओं का चयन ई० ए० एस० के अन्तर्गत गरीबों के द्वारा नहीं किया जा रहा है? तीसरा, मेरा प्रश्न है कि जवाहर रोजगर योजना के अन्तर्गत कितनी राशि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को डायरेक्ट लाभ पहुंचान के लिए आवंटित की जाती है–कितने प्रतिशत–और क्या उसका अनुसरण किया जाता है?

SHRI BABAGOUDA PATIL: Sir, the estimation of poverty is done by the Planning Commission. So it is the duty of the Planning Commission to see on which criteria the extent of poverty is to be identified. Though the number of poor families is coming down, but in absolute terms, the number remains the same. With regard to the second question, the EAS is a demand driven programme and this programme is implemented by all the DRDAs in the lean season of agriculture by which 40 per cent of the poor SC/ST population is benefited.

श्री राघवजी : सभापति जी, मध्य प्रदेश के गांव गरीबी निवारण योजनाओं की राशि के लिए तरसते रहते हैं। इसके बावजूद भी मध्य प्रदेश की सरकार जो राशि केन्द्र सरकार से मिलती है उसका पूरा उपयोग नहीं कर पाती। माननीय मंत्री जी ने कहा है कि 10 लाख कुओं वाली योजना में जो खर्च किया गया है वह संतोषप्रद है। पता नहीं कहां से संतोषप्रद है। आपने जो फिगर्स दिए हैं उसमें 55 करोड़ और 2 लाख रूपये का आवंटन था जिसमें जो अनुपयुक्त हुआ है वह राशि 2,643 लाख है। 50 प्रतिशत से अधिक राशि का उपयोग नहीं हुआ है। तो यह संतोषप्रद कैसे माना जा सकता है। मेरे प्रश्न का दूसरा भाग यह है कि इन योजनाओं में राज्य सभा के सदस्यों को सम्मिलित नहीं किया जाता है। तो क्या सरकार इस बात का आश्वासन देगी कि राज्य सभा के सदस्यों को भी इन योजनाओं में शामिल करें और जिला परिषद में उनका एक सदस्य मनोनीत किया जाए।

SHRI BABAGOUDA PATIL: Sir, I have stated in my answer that except in the Million-Well Scheme and the DWCRA, the performance of the State Government is good in the implementation of all these schemes. This is what I have stated in my answer. I am not satisfied with with the implementation of the Million Well Scheme and the DWCRA. As far as involving the Members of Rajya Sabha is concerned, I will consider this suggestoin.

SHRI GOVINDRAM MIRI: Sir, as per my knowledge and information, the money which is being spent is not going to the real beneficiaries. This money is being misused by the State Governments. Sir, I would like to know from the hon. Minister as to what concrete steps have been taken or are being taken to see to it that this money is used properly and it goes to the real beneficiaries. I would also like to know from the hon. Minister—I am not talking of the Members of Rajya Sabha, but of the Members of Parliament—whether he is going to associate the Members of Parliament in the implementation of these schemes.

SHRI BABAGOUDA PATIL: Sir, in every district, there is a Monitoring and Vigilance Cell. The Members are also members of the Vigilance Committee. . . (*Interruptions*) They can monitor. . . . (*Interruptions*) . .

श्री जनार्दन यादव : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि गरीबी उन्मूलन की जितनी योजनाएं केन्द्रीय सरकार ने भेजी हैं, क्या उसके लिए मध्य प्रदेश में गरीबों का प्रतिशत तथा हूअ है, अर्थात् मध्य प्रदेश

में गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों की कितनी संख्या है ?

SHRI BAAGOUDA PATIL: I need a separate notice for this.

श्री जनार्दन यादव : सभापति महोदय, जब गरीबी उन्मूलन स्वीकार किया गया है तो मध्य प्रदेश में गरीबी रेखा से नीचे कितने लोग हैं यह तो सरकार के ध्यान में रहना चाहिए। सरकार के पास आंकड़े रहने ही चाहिएं, नहीं तो गरीबी उन्मूलन कैसे होगा ?

प्रो० रामलखन सिंह वर्मा : सभापति महोदय, मैं इस प्रश्न के संबंध में माननीय मंत्री जी से मालूम करना चाहता हूं कि मिलियन वैल्ज स्कीम, दबावरा या जे० आर० वाई० जैसी जो तमाम केन्द्रीय योजनाएं हैं गरीबी उन्मूलन के लिए या रोजगार सृजन के लिए, ये जो योजनाएं जिले में होती हैं बहुत से प्रदेशों में मान्यवर अभी भी इसका चेयरमैन जिलाधिकारी होता है और इसमें जो जनप्रतिनिधि, मैम्बर आंफ पार्लियामेंट अथवा जो एम० एल० एज०, एम० एल० सीज होते हैं, वे उसके सदस्य होते हैं और यह मेरी निश्चित जानकारी है कि इसमें जिलाधिकारी इन योजनाओं का दुरुपयोग करते हैं की कुछ ऐसी योजनाएं हैं जिसमें जिलाधिकारी और जो संबंधित विभाग होने हैं हैं उनके अधिकारी सदस्य होते हैं और किसी जन प्रतिनिधि को उसका चेयरमैन बनाया जाता है। तो मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि इस प्रकार की योजनाएं जो केन्द्रीय योजनाएं हैं इनमें जनप्रतिनिधियों का ज्यादा सहयोग हो, ज्यादा पार्टिसिपेशन हो, इसलिए इन योजनाओं का चेयरमैन बाय रोटेशन क्या जनप्रतिनिधियों को एम० एल० एज० और एम० पीज को बनाया जाएगा और जिलाधिकारी और दूसरे अधिकारियों को उसका सदस्य, यह मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं ?

SHRI BABAGOUDA PATIL: Sir, we are persistently requesting the State Governments to appoint Zilla Panchayat Chairmen as the Presidents of the DRDAs. Some State Governments are not listening to our advice. And, MLAs and MPs are the Members of monitoring and vigilance Committees.

श्रीमती वीणा वर्मा : सभापति महोदय, ज्यादातर शिकायतें जवाहर रोजगार योजना के बारे में यह रहती है कि मस्टर रोल बदल दिए जाते हैं, उनमें कुछ गड़बड़ियां की जाती हैं और महिलाओं तथा पुरुषों को बराबर दिहाड़ी नहीं दी जाती है। महिलाओं को कम दिहाड़ी दी जाती है। तो मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या कोई ऐसी शिकायतें भी हैं कि महिलाओं को कम दिहाड़ी दी गई है ? मेरे पास कुछ सूची है, मध्य प्रदेश के बारे में नहीं है, आन्ध्र प्रदेश और केरल की है, उसमें महिलाओं को कम दिहाड़ी दी जाती है। दूसरी चीज , जो पंचायती राज के द्वारा, ग्राम पंचायतों के द्वारा जो जे. आर. वाई. लागू होनी है, तो बहुत से प्रदेशों में अभी तक पंचायती राज ही लागू नहीं है, वहां पर किस तरह से इसे लागू करेंगे ?

श्री सभापति : नहीं-नहीं, यह मध्य प्रदेश का सवाल है।

श्रीमती वीणा वर्मा : यह मध्य प्रदेश के बारे में ही मैं पूछ रही हूं कि क्या मध्य प्रदेश से ऐसी सूचना भी है कि वहां महिलाओं को कम दिहाड़ी दी जाती है और मस्टर रोल के बारे में केन्द्रीय सरकार क्या कोई ऐसी मॉनिटरिंग एजेंसी बनायेगी या कोई योजना लागू करेगी जिससे कि यह मानिटरिंग का कार्य हो सके और पता चले सके कि यह सब व्यवस्थाएं सही हैं या नहीं, या कोई गड़बड़ियां तो नहीं हैं ?

SHRI BABAGOUDA PATIL: Mr. Chairman, Sir, if there is any complaint regarding the wages given to the women, definitely, we will look into that and we will take action. Regarding the second question, I would like to submit that there is no such provision to send a separate team from the Central Government to monitor the programmes. There is no such provision.

श्री त्रिलोकी नाथ चतुर्वेदी : सभापति महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह जानना

चाहूंगा कि जे.आर.वाई. के संबंध में जो अनुभव मध्य प्रदेश में हुआ था अन्य राज्यों में हो रहा है और पब्लिक एकाउंट्स कमेटी ने उसमें कुछ संशोधन और परिवर्तन के लिए सुझाव दिए हैं ? क्या उस के आधार पर वे इस योजना को अधिक प्रभावी बनाने के लिए कमेटी बिठाएंगे या किसी टेक्नीकल कंसल्टेंट से इस संबंध में विचार-विमर्श कर के पार्लियामेंट को सूचित करेंगे ?

SHRI BABAGOUDA PATIL: Sir, we will definitely take into consideration the recommendations of the Consultative Committee meeting, the recommendations of the Standing Committee and also the recommendations of the hon. Member.

Import of spare parts of IAF

*249. PROF. VIJAY KUMAR MALHOTRA:
SHRI O. RAJAGOPAL:†

Will the Minister of DEFENCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that spare parts for Air Force are imported;

(b) if so, the quantum of spare parts imported and indigenously manufactured; and

(c) the plan to manufacture spare parts indigenously not only to cut down costs, but also to become self-dependant?

THE MINISTER OF DEFENCE (SHRI GEORGE FERNANDES): (a) and (b) During the year 1997-98 spare parts worth Rs. 1652.15 crores have been imported and worth Rs. 1066.67 crores manufactured indigenously.

(c) With the aim of achieving the twin goals of self reliance and cutting dowr. costs, efforts are being made to manufacture increasing quantity of spares within the country, by HAL and private agencies. IAF has taken up major programmes for indigenisation of spares and components required for maintenance of aircraft and helicopters of Russian origin. Inhouse indigenisation is being undertaken at Base Repair Depots. Regular workshops, exhibitions and seminars are also being organised in collaboration with the industry for cooperation and active involvement/participation in the indigenisation effort. So far, over 27,600 items of fighter aircraft and helicopters of Russian origin have been indigenised.

SHRI O. RAJAGOPAL: Sir, this question relates to the import of spare parts for the Air Force. We find that even after 50 years of independence, the cost of import is Rs. 1,652 crores more as compared to the cost of items manufactured in the country. Why is there so much gap? Do we have any plan to see that within some stipulated period we can have 100 per cent self-reliance in this matter? Is it possible? Then, he has only mentioned that items worth so many crores of rupees have been imported. I would like to know what percentage is it. I would also like to know whether the percentage of import is going down or it is going up.

SHRI GEORGE FERNANDES: Sir, in so far as the percentage of imports is concerned there is a constant increase in indigenisation. The average process of expansion of indigenisation varies between 5 and 10 per cent. But in so far as the main aspect of the supplementary question is concerned, that is, why we have not been able to indigenise during the last 50 years, there are areas where indigenisation is not difficult; and that has been done. But there

†The question was actually asked on the floor of the House by Shri O. Rajgopal.